

भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2135
दिनांक 12.03.2025 को उत्तर देने के लिए

खनिज अन्वेषण

2135. श्री जशुभाई भलुभाई राठवा:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में और विशेष रूप से राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा रिपोजिटरी (एनजीडीआर) पोर्टल के माध्यम से खनिज अन्वेषण को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की गई प्रमुख पहलों का ब्यौरा क्या है तथा अन्वेषण संबंधी व्यय के लिए नई प्रतिपूर्ति योजनाएं क्या हैं; और

(ख) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) किस प्रकार खनिज अन्वेषण में सहायता कर रहा है और खनन क्षेत्र में स्टार्ट-अप और एमएसएमई के बीच नवाचार को बढ़ावा दे रहा है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री
(श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) : राष्ट्रीय भूवज्ञान डेटा कोष (एनजीडीआर) पोर्टल एक क्लाउड-आधारित पोर्टल है जिसे सभी आधारभूत और गवेषण-संबंधित भू-वैज्ञानिक डेटा को एकल जीआईएस प्लेटफॉर्म पर डालकर देश के खनिज गवेषण कवरेज को तीव्र करने और सुवधाजनक बनाने, सभी हितधारकों के लिए इसे उपलब्ध कराने और एकल वंडो प्रणाली में भू-स्थानिक डेटा का प्रसार करने के लिए बनाया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) एनजीडीआर पोर्टल का नोडल एजेंसी है और इसे राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (एनएमईटी) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। वर्तमान में, जीएसआई की 9767 रिपोर्टें, हितधारकों की 1303 रिपोर्टें और

35 से अधिक परतों से संबंधित डेटा पंजीकृत उपयोगकर्ताओं हेतु डाउनलोड के लिए एनजीडीआर पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

एनएमईटी ने गवेषण अनुज्ञप्ति धारकों के लिए गवेषण व्यय आंशिक प्रतिपूर्ति योजना शुरू की है जहाँ एनएमईटी 20 करोड़ रुपये की सीमा के साथ प्रत्यक्ष लागत के 50% तक गवेषण अनुज्ञप्ति धारकों द्वारा किए गए गवेषण व्ययों की आंशिक प्रतिपूर्ति करेगा। एनएमईटी 8 करोड़ रुपये की सीमा के साथ गवेषण के लिए किए गए 50% प्रत्यक्ष लागत तक गवेषण व्ययों की आंशिक प्रतिपूर्ति की योजना से संयुक्त अनुज्ञप्ति धारकों को सहायता भी करता है।

इसके अतिरिक्त, यदि ब्लॉक को जी4 से जी3 चरण में अद्यतित किया जाता है तो एनएमईटी सोना, आधार धातुओं, अन्य बहुमूल्य खनिजों, सामरिक महत्वपूर्ण खनिजों और उर्वरक खनिजों के लिए ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में जी4 मलों के लिए परियोजना की स्वीकृत लागत का 25% गवेषण प्रोत्साहन भी प्रदान करता है।

(ख) : अगस्त 2015 में अपनी स्थापना के बाद से, एनएमईटी ने 2846.30 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से आधारभूत सर्वेक्षण के साथ-साथ क्षेत्रीय और वस्तुतः गवेषण परियोजनाएं, केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता, राज्यों को प्रोत्साहन तथा एनईए और एनपीईए द्वारा खनिज गवेषण आदि सहित 503 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है। एनएमईटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) प्रज्म कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को वित्त पोषित कर स्टार्ट-अप्स, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में अनुसंधान और नवाचार तथा अलग-अलग नवप्रवर्तकों को प्रोत्साहित कर रहा है। आज तक, एनएमईटी ने 28.43 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से 22 परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है।
